Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का संकल्प लें

वर्ष-19, अंक-16 16-31 अगस्त, 2024 (पाक्षिक) ₹20

हर घर तिरंगा

हर घर तिरंगा: एक यादगार जन आंदोलन

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 27 जुलाई, 2024 को मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा भाजपा शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्रीगण

राजकोट (गुजरात) में 10 अगस्त, 2024 को 'तिरंगा यात्रा' में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा एवं गुजरात भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेतागण

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 28 जुलाई, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 112वें एपिसोड को सुनते पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

चंडीगढ़ में 04 अगस्त, 2024 को 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

चंडीगढ़ में 04 अगस्त, 2024 को हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों 'ई-सक्षमता' एवं 'न्याय सेतु' का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 प्रत्येक नागरिक 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का संकल्प लें : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 अगस्त, 2024 को गुजरात के राजकोट से भाजपा के राष्ट्रव्यापी एवं जन-जन के कार्यक्रम 'तिरंगा यात्रा' का शुभारंभ किया और हरी...

11 प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की...

12 'पिछले 10 वर्षों में रेलवे और राजमार्गों के बजट में 8 गुना वृद्धि हुई'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उपस्थित गणमान्यों को संबोधित करते हुए कहा...

14 भारत आज खाद्य अधिशेष वाला देश है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र (एनएएसी) परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों...

26 हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई 'कर व्यवस्था' से मध्यम वर्ग को लाभ होगा: वित्त मंत्री

माननीय प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण इस देश में एक सरल, कुशल, निष्पक्ष और...

वैचारिकी
भारतीय जनसंघ ही क्यों? / **डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी** 23

लेख
भारतीय कृषि का अमृतकाल / **शिवराज सिंह चौहान** 24

श्रद्धांजलि
जननेता 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी 21

मन की बात
खादी की बिक्री बढ़ी 400 प्रतिशत, पहली बार कारोबार डेढ़ लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा: नरेन्द्र मोदी 32

अन्य
पूरे उत्साह के साथ भाजपा चलाएगी राष्ट्रव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान 09
प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की प्रगति की सराहना की 16
जीईएम पोर्टल से सार्वजनिक खरीद 9.82 लाख करोड़ रुपये के पार 17
936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मिली मंजूरी 19
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मिली मंजूरी 20
अनुच्छेद 370 और 35(ए) के निरस्तीकरण के 5 वर्ष 22
लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 28
'18वीं लोकसभा' के गठन के बाद संसद का पहला बजट सत्र समाप्त 30
प्रधानमंत्री ने एससी/एसटी के भाजपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

मुझे खुशी है कि #एक_पेड़_मां_के_नाम अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर के लोगों ने एक बड़ी पहल करते हुए एक दिन में 12 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर देशभर के लोगों के लिए मिसाल कायम की है।

(28 जुलाई, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

2014 में जब हमारी सरकार आई तब विश्व स्वास्थ्य सभा में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संदर्भ में चिंता व्यक्त की जाती थी। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'आयुष्मान भारत' के तहत हम दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने में सफल रहे हैं।

(05 अगस्त, 2024)

अमित शाह

प्रधानमंत्री आवास योजना बीते 9 सालों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 10 लाख करोड़ रुपए की लागत की 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' को मंजूरी दी है। आगामी 5 सालों में इस योजना से 1 करोड़ शहरी गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार लाभान्वित होने वाले हैं। साथ ही, इस योजना के तहत निर्मित होने वाले सारे आवासों में संयुक्त या स्वतंत्र रूप से महिलाओं के स्वामित्व की घोषणा नारी शक्ति को और भी सशक्त बनाने वाली है।

(09 अगस्त, 2024)

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में सम्मिलित हुआ। प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में भाजपा की सरकारें 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। इस संकल्प को साकार करने के लिए सभी संभव कदम उठाने के प्रति हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

(28 जुलाई, 2024)

बी.एल. संतोष

भाजपा की स्थापना के समय से ही निःस्वार्थ सेवा इसकी पहचान रही है। इसी भावना के अनुरूप केरल भाजपा के कार्यकर्ता वायनाड में केंद्रीय और राज्य राहत दलों की मदद कर रहे हैं।

(01 अगस्त, 2024)

निर्मला सीतारमण

हमारे बारे में एक बात कही जाती है कि हम मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और वे हमसे 'नाराज' हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूं कि वे समझें कि इस देश में पहले की सरकारों में 98 प्रतिशत टैक्स था और इन सरकारों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की कभी परवाह नहीं की। ऐसी सरकारें आयीं जिन्होंने आपातकाल लगाया। और 2004-14 के बीच जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको देखते हुए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जनता का भला तभी होता यदि जनता इस दौरान अपना पैसा अपनी तिजोरियों में ही रखती, बजाय यह पैसा कुछ वंशवादी नेताओं की जेबों में गया।

(07 अगस्त, 2024)

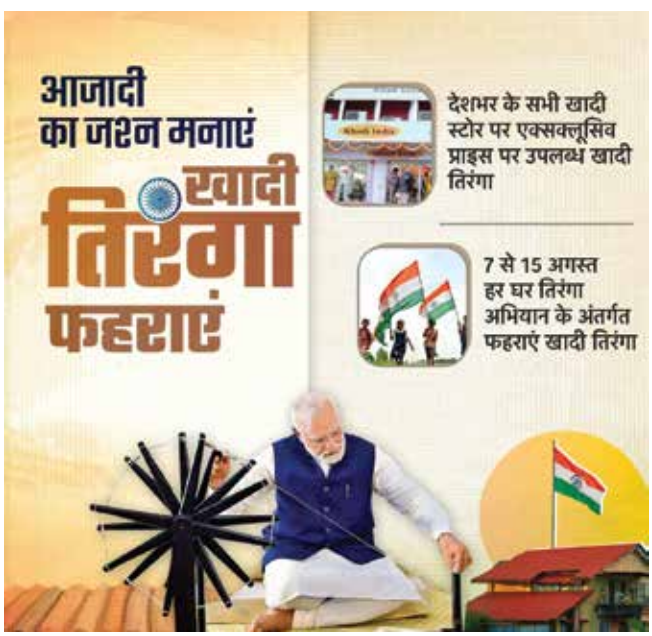

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (26 अगस्त)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

आशा व विश्वास का प्रतीक 'हमारा तिरंगा'

अपनी शुरुआत से ही 'हर घर तिरंगा अभियान' लोगों में राष्ट्रीय भावना एवं देशभक्ति जगाने वाला एक जन-अभियान बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर बदल कर तिरंगा लगाने की अपील को भारी जनसमर्थन मिला है। करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़कर स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व में नए रंग भर रहे हैं, साथ ही उत्साह से भरे वातावरण में 'एकजुटता एवं भाईचारा का संदेश' भी गूंज रहा है। 'विकसित भारत' की यात्रा में देश का तिरंगा आशा एवं विश्वास का प्रतीक बन गया है। इस अभियान में बच्चे, महिलाएं एवं युवाओं की भारी भागीदारी से यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि आने वाली पीढ़ी विकास, शांति, एकता, परस्पर विश्वास एवं भाईचारा के पथ पर अग्रसर है। यह अभियान देश के राष्ट्रनायकों को याद कर उनके बलिदानों से प्रेरणा लेने का भी अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्मारकों पर स्वच्छता अभियान तथा महानायकों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के कार्यक्रम, पूरे देश को देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर देते हैं। जहां 'हर घर तिरंगा अभियान' से सराबोर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को पूरे उमंग एवं उत्साह से मनाता है, वहीं 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' विभाजन की त्रासदी को याद कर उन लाखों लोगों को, जो इसकी भेंट चढ़ गए एवं उन करोड़ों लोगों को, जो अपने घर-बार से पलायन को मजबूर हुए, उनके परिवारों के साथ दर्द बांटने एवं पीढ़ियों तक के उनके संघर्षों एवं बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है।

> **'विकसित भारत' का लक्ष्य 'विकसित प्रदेशों' के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नीति आयोग को आकांक्षी जिले कार्यक्रम, निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण की योजना, राज्यों में नदियों का ग्रीड, जनसंख्या प्रबंधन योजना एवं 2047 के लिए 'राज्यों हेतु दृष्टि' पर कार्य करने का आह्वान किया**

संसद का बजट सत्र, लोकसभा में 136 प्रतिशत एवं राज्य सभा में 118 प्रतिशत की कार्य उत्पादकता प्राप्त करने में सफल रहा। जहां बजट पर हुई, चर्चा में दोनों सदनों में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया, संसद में कई विधेयक लाए गए एवं पारित हुए। बहुचर्चित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 जो वक्फ कानून, 1995 को संशोधित कर वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित एवं निरंकुश शक्तियों को न्यायसंगत बनाते हुए उनके प्रबंधन एवं प्रशासन में सुधार करने हेतु लाया गया। कांग्रेसनीत विपक्ष का यह दावा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रावधानों को कमजोर कर मुसलमानों के हितों की अनदेखी करता है, पूर्णतः निराधार है। वास्तव में, वर्तमान कानून वक्फ बोर्ड को अतीत के दावों के आधार पर किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' घोषित करने का एकतरफा अधिकार देता है। वर्तमान का वक्फ कानून, 1995 ने वक्फ बोर्ड को ऐसी असीमित शक्तियां दे दी हैं जिनसे आम मुसलमानों एवं उनकी संपत्तियों के साथ-साथ गैर-मुस्लिमों की भी संपत्तियां प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं, 2013 एवं 2014 में तत्कालीन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने एक के बाद एक, दो प्रयास किए जिनसे वक्फ बोर्ड को अथाह शक्तियों के साथ-साथ कड़े दंडात्मक कानूनी अधिकार भी मिल जाते हैं। अब जबकि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, कांग्रेसनीत विपक्ष से अपेक्षित है कि वे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठे तथा वक्फ संपत्तियों के प्रशासन एवं प्रबंधन; मुस्लिम महिलाओं, बच्चे, गरीब एवं पिछड़े के हित में हो, इसे सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएं।

हाल ही में संपन्न नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य 'विकसित प्रदेशों' के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने नीति आयोग को आकांक्षी जिले कार्यक्रम, निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण की योजना, राज्यों में नदियों का ग्रीड, जनसंख्या प्रबंधन योजना एवं 2047 के लिए 'राज्यों हेतु दृष्टि' पर कार्य करने का आह्वान किया। सीआईआई द्वारा आयोजित 'विकसित भारत की ओर यात्राः केंद्रीय बजट 2024-25 के पश्चात् सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछले दस वर्षों में किए गए कार्यों के 'स्पीड एवं स्केल', राजनैतिक इच्छाशक्ति, नीयत एवं प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश की जनता की आकांक्षाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लिए सर्वोपरि हैं और उसके लिए वे 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

राष्ट्रव्यापी 'तिरंगा यात्रा' का शुभारंभ

प्रत्येक नागरिक 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का संकल्प लें : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 अगस्त, 2024 को गुजरात के राजकोट से भाजपा के राष्ट्रव्यापी एवं जन-जन के कार्यक्रम 'तिरंगा यात्रा' का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। वे तिरंगा यात्रा के सहभागी भी बने। इससे पहले उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और देश की एकता एवं अखंडता के अग्रदूत सरदार वल्लभभाई पटेल का भी स्मरण किया। ज्ञात हो कि 'हर घर तिरंगा' यात्रा 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य हर घर, हर प्रतिष्ठान में तिरंगा फहराने का उत्सव मनाना है जो राज्य भर में एकता और देशभक्ति का संदेश फैलाने का काम करेगा। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, मेयर श्री नैना बेन, कैबिनेट मंत्री श्री राघव पटेल, श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री विनोद चावडा सहित पार्टी के अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि गुजरात की भूमि वीरों, संतों और समाज सुधारकों की भूमि है। आज तिरंगा यात्रा के अवसर पर चारों ओर तिरंगा देखकर आजादी की लड़ाई के कालखंड की याद आती है। आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश और गुजरात की भूमि कभी भी

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर तिरंगे वाली प्रोफाइल पिक्चर बदलने का किया आग्रह

हरघरतिरंगा डॉट कॉम पर तिरंगे के साथ सेल्फी साझा करने का भी आग्रह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौ अगस्त को नागरिकों से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगे के साथ बदलें। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगे में बदल दिया है। उन्होंने हर घर तिरंगा आंदोलन को एक यादगार जन आंदोलन बनाने के लिए देश के सभी लोगों से ऐसा करने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने सभी से हरघरतिरंगा डॉट कॉम पर तिरंगे के साथ सेल्फी साझा करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, "इस साल का स्वतंत्रता दिवस काफी करीब है। आइए, हम सब मिलकर #हरघरतिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करते हुए हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में साथ दें और हां, हरघरतिरंगा डॉट कॉम पर अपनी सेल्फी अवश्य साझा करें।"

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकती। आज जब हम इस तिरंगा यात्रा पर निकल रहे हैं, तो हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों की याद आती है। यह यात्रा औपनिवेशिक शासन के काले दौर को भी याद दिलाती है। जब हम उस युग पर विचार करते हैं, तो हमें उस स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत को आकार देने में गुजरात के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना चाहिए, जिसे हम आज जानते हैं। आज के दिन हम सरदार वल्लभभाई पटेल को नहीं भूल सकते। आजादी के समय यह देश 562 रियासतों में बंटा हुआ था। उन्हें जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़कर 'मेरा भारत महान' बनाया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी गुजरात की पवित्र माटी से आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमृत काल से लेकर 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। विकसित भारत की यात्रा में गुजरात महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तिरंगा यात्रा की शुरुआत राजकोट से हुई है। कल सूरत में, फिर वडोदरा और अहमदाबाद में इस तरह की बड़ी-बड़ी तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। ये तिरंगा यात्रा हर तालुक और मंडल में पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा का ये क्रम 15

मुख्य बातें

- तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सद्भाव एवं स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़े सेनानियों को याद करना है। तिरंगा देशवासियों की आन-बान और शान है। इसे हमें सदैव बरकरार रखना है
- सरदार वल्लभभाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और नेता जी सुभाष चंद्र बोस का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता लेकिन कांग्रेस को केवल एक ही परिवार याद रहता है
- कांग्रेस का कोई भी नेता केवड़िया में 'स्टैचू ऑफ यूनिटी' पर आज तक फूल चढ़ाने तक नहीं गया। कांग्रेस नेता नकली राष्ट्रभक्ति करके राजनीतिक चश्मे से समाज को देखने वाले, राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटने वाले और अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं
- कांग्रेस ने हजारों-लाखों ऐसे मनीषियों-महापुरुषों के योगदान को भुला दिया जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया
- तिरंगा यात्रा का लक्ष्य और उत्सव तभी ही पूर्ण होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक देश को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेगा

आज गुजरात के राजकोट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रव्यापी #HarGharTiranga अभियान के अंतर्गत आयोजित भव्य 'तिरंगा यात्रा' में शामिल होकर स्थानीय लोगों को संबोधित किया। यह अभियान आगामी 15अगस्त तक देशभर के हर जिले, तालुका, गांव व घर तक पहुंचेगी। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देश के जन-जन अपने घर व प्रतिष्ठान में राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराकर मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल के पावन अवसर पर 'विकसित भारत' निर्माण का संकल्प लिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक यात्रा के सहभागी हैं।

आइए, हम सभी इस राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हों और स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के साथ उन वीर बलिदानियों को नमन करें जिन्होंने देश की संस्कृति, स्वतंत्रता व सम्मान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जय हिंद!

- जगत प्रकाश नड्डा

अगस्त तक चलता रहेगा। 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम को हमें एकजुट होकर सफल बनाना है।

उन्होंने कहा कि मैं युवा साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए देश के हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और लाखों परिवारों ने अपना सुख-चैन त्याग कर योगदान दिया है। देशभक्ति से ओतप्रोत होकर देश की जनता ने दिन-रात एक करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 9 अगस्त (जो कल थी) को भी भारत भूल नहीं सकता। इसी दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये मात्र एक नारा नहीं रहा, ये घर घर की आवाज बन गई और घर-घर से अंग्रेजों को चुनौती दी गई कि भारत हमारा देश है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद एक के बाद एक आंदोलन चलाए गए और 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश की जनता को एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने के संकल्प पूरा करना है। देश के वीरों ने 1947 में अपना बलिदान देकर हमें जो सुरक्षा और शांति पूर्ण जीवन दिया है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां आए हुए सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदीजी के आह्वान पर अमृतकाल का उपयोग करके 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के

पूरे उत्साह के साथ भाजपा चलाएगी राष्ट्रव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान

भाजपा द्वारा 11, 12 एवं 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जुलाई, 2024 को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 112वें संस्करण में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया था। 2022 से पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी 'हर घर तिरंगा' अभियान को देश के जन-जन के साथ मनाती है। इस बार भी देश के हर नागरिक बढ़-चढ़कर पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान मनाने वाले हैं। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जुलाई, 2024 को इस अभियान के संदर्भ में परिपत्र जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ के नेतृत्व में सात सदस्यीय कमिटी की रचना कर इस राष्ट्रीय महोत्सव को सफल बनाने हेतु पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस सात सदस्यीय कमिटी में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानिथी श्रीनिवासन, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अनिल एंटनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, श्री त्रिलोक जामवाल और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु प्रकाश पासवान शामिल हैं।

2022 से पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी 'हर घर तिरंगा' अभियान को देश के जन-जन के साथ मनाती है। इस बार भी देश के हर नागरिक बढ़-चढ़कर पूरे देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान मनाने वाले हैं। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जुलाई, 2024 को इस अभियान के संदर्भ में परिपत्र जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ के नेतृत्व में सात सदस्यीय कमिटी की रचना कर इस राष्ट्रीय महोत्सव को सफल बनाने हेतु पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए थे

श्री नड्डा ने 29 जुलाई को परिपत्र जारी करते हुए 'हर घर तिरंगा' अभियान की सफलता के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में देश भर में भाजपा की देश भर में प्रदेश पदाधिकार्यों, मोर्चा की टीमों, जिलाध्यक्षों एवं जिला टीम की बैठकें लगातार हो रही हैं। इसी तरह इस अभियान के संबंध में जिला समितियों और मंडल समितियों की बैठकें भी हो रही हैं। साथ ही, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सभी प्रदेश अपने सभी भाजपा के जन प्रतिनिधियों सांसद, विधायक, एमएलसी, मेयर, जिला परिषद् अध्यक्ष, ब्लॉक परिषद् अध्यक्ष, नगर परिषद् अध्यक्ष के साथ वर्चुअल बैठकें भी कर रहे हैं। इस तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी जन-प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी, शक्ति केंद्र और बूथ टीमों के कार्यकर्ता, दिन-रात युद्धस्तर पर लगे हुए हैं।

पार्टी द्वारा 11, 12 एवं 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा मोर्चा प्रमुख भूमिका में रहेगा। 12, 13 एवं 14 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता सेनानियों एवं युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण अर्पित की जाएगी। 14 अगस्त को देश के सभी जिलों में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा और मौन मार्च का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 13, 14 एवं 15 अगस्त को सभी घरों में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता, जन-प्रतिनिधि भाग लेंगे। ■

बाद से पूरी दुनिया का अर्थतंत्र लड़खड़ा गए, मगर इन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई। आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। स्टील विनिर्माण में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 10 साल पहले भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन, कोरिया, जापान, चीन और ताइवान में बनाए जाते थे, मगर आज हर मोबाइल का विनिर्माण भारत में हो रहा है। पहले भारत के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थीं, आज हमारा देश पूरी दुनिया में बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रह है और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है।

श्री नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में सरदार वल्लभभाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस को यह बलिदान दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस को केवल एक ही परिवार याद रहता है। कांग्रेस के चश्मे में एक ही परिवार दिखता है। कांग्रेस ने हजारों-लाखों ऐसे मनीषियों-महापुरुषों के योगदान को भुला दिया, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया। कांग्रेसियों को याद रहता है तो सिर्फ एक परिवार। कांग्रेस का कोई भी नेता केवड़िया में 'स्टैचू ऑफ यूनिटी' पर आज तक फूल चढ़ाने तक नहीं गया। कांग्रेस नेता नकली राष्ट्रभक्ति करके राजनीति के चश्मे से समाज को देखने वाले लोग हैं। ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटने वाले और अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं, लेकिन देश की जनता और नौजवान विपक्ष को सच से अवगत करा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि देश को विकसित भारत के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। तिरंगा यात्रा का लक्ष्य और उत्सव तभी ही पूर्ण होगा, जब देश का प्रत्येक नागरिक देश को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण का संकल्प लेगा। ■

'हर घर तिरंगा' अभियान 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 8 अगस्त को घोषणा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 9 से 15 अगस्त तक तीसरा 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा।

नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' फहराने के लिए प्रोत्साहित करके नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों में तिरंगा फहराने और झंडे के साथ एक सेल्फी क्लिक करने और इसे harghartiranga.com पर अपलोड करने का आग्रह किया।

अभियान का एक मुख्य आकर्षण संसद सदस्यों की विशेष तिरंगा बाइक रैली है, जो 13 अगस्त को सुबह 8 बजे दिल्ली में आयोजित की जाएगी

इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू किया गया 'हर घर तिरंगा' अभियान एक जन आंदोलन बन गया है, जिसे देश भर में समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनाया है। 2022 में 23 करोड़ से अधिक घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और 6 करोड़ लोगों ने ध्वज के साथ अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर अपलोड की। 2023 में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक सेल्फी अपलोड की गईं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अभियान की सफलता सुनिश्चित करते हुए समारोह में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

प्रमुख उद्योग भागीदार— ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रेलवे, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी सूचना के प्रसार और अभियान को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। देशभर में स्वयं सहायता समूह बड़े पैमाने पर झंडे के उत्पादन और उपलब्धता में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सहयोगात्मक प्रयास राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल रहा है तथा यह भारत के लोगों का, भारत के लोगों द्वारा एक और महत्वपूर्ण उत्सव है।

अभियान का एक मुख्य आकर्षण संसद सदस्यों की विशेष तिरंगा बाइक रैली है, जो 13 अगस्त को सुबह 8 बजे दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह रैली भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली से शुरू होगी और इंडिया गेट से होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर समाप्त होगी।

प्रधानमंत्री ने 28 जुलाई, 2024 को अपने नवीनतम मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और 'हर घर तिरंगा' की परंपरा को जारी रखने का आग्रह किया, जिसमें पिछले दो वर्षों में जनता की व्यापक भागीदारी देखी गई है। ■

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की

केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से 'विकसित भारत@2047' का सपना साकार होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई थी। इसमें 20 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र के सहयोग और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया।

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दस वर्षों में विकास की गति को बनाए रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2024 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि अब सरकार और सभी नागरिकों का सामूहिक लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हमारे देश ने पिछले दस वर्षों में सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके पहले ही काफी प्रगति की है। पहले से मुख्य रूप से आयात पर निर्भर एक देश 'भारत' अब दुनिया को कई उत्पाद निर्यात करता है। देश ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्ट-अप और खेल जैसे व्यापक क्षेत्रों में विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 140 करोड़ नागरिकों के आत्मविश्वास और उत्साह की सराहना की, जो हमारे देश की प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति है।

विकसित राज्यों के माध्यम से साकार होगा 'विकसित भारत' का विजन

श्री मोदी ने कहा कि यह बदलाव का दशक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में ढेरों अवसर लेकर आया है। उन्होंने राज्यों को इन अवसरों का उपयोग करने और नीति निर्माण और क्रियान्वयन में नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से विकास के लिए अनुकूल नीतियां बनाने और शासन के कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के विजन को विकसित राज्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है और विकसित भारत की आकांक्षा जमीनी स्तर यानी प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक राज्य और जिले को 2047 के लिए एक विजन बनाना चाहिए, ताकि 2047 में विकसित भारत को साकार किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इसकी सफलता की कुंजी मापन योग्य मापदंडों की निरंतर और ऑनलाइन निगरानी थी, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपने कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई।

श्री मोदी ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण पर जोर दिया, क्योंकि दुनिया कुशल मानव संसाधन के लिए भारत की ओर अनुकूल रूप से देख रही है।

उन्होंने राज्यों को निवेशक के अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने नीति आयोग को मापदंडों का एक 'निवेश-अनुकूल चार्टर' तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें निवेश आकर्षित करने के लिए लागू की जाने वाली नीतियां, कार्यक्रम और प्रक्रियाएं शामिल होंगी। उन्होंने निवेश आकर्षित करने के लिए केवल प्रोत्साहन के बजाय कानून और व्यवस्था, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व पर भी जोर दिया।

श्री मोदी ने जल संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड बनाने को प्रोत्साहित किया।

कृषि में उत्पादकता और विविधीकरण बढ़ाने पर जोर

श्री मोदी ने सभी राज्यों को कृषि में उत्पादकता और विविधीकरण बढ़ाने तथा किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सकता है, कम लागत के कारण किसानों को बेहतर और त्वरित लाभ मिल सकता है और उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार भी उपलब्ध हो सकता है।

श्री मोदी ने राज्यों को भविष्य में वृद्धों के मुद्दों का समाधान करने के लिए जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों का क्षमता निर्माण करने को कहा और उन्हें इसके लिए क्षमता निर्माण आयोग के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। ■

प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत की ओर यात्रा: केंद्रीय बजट 2024-25 के पश्चात् सम्मेलन' को किया संबोधित

'पिछले 10 वर्षों में रेलवे और राजमार्गों के बजट में 8 गुना वृद्धि हुई'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 'विकसित भारत की ओर यात्रा: केंद्रीय बजट 2024-25 के पश्चात् सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन का उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और थिंक टैंकों सहित अन्य क्षेत्रों से एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लिया, जबकि देश और विदेश में स्थित विभिन्न सीआईआई केंद्र इस कार्यक्रम से जुड़े थे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उपस्थित गणमान्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश के नागरिक जीवन के हर पहलू में स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं और उत्साह से भरे होते हैं तो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के आमंत्रण के प्रति आभार व्यक्त किया।

पूंजीगत व्यय में पांच गुने से अधिक की वृद्धि: आज 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक

हाल ही में पेश किए गए बजट के कुछ तथ्य सामने रखते हुए श्री मोदी ने मौजूदा 48 लाख करोड़ रुपये के बजट की तुलना 2013-14 के 16 लाख करोड़ रुपये के बजट से की, जिसमें अब तीन गुना की वृद्धि है। संसाधन निवेश का सबसे बड़ा पैमाना पूंजीगत व्यय 2004 में 90 हजार करोड़ रुपये था, जो 2014 तक के 10 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये हो गया, यानी दोगुना वृद्धि जबकि इसकी तुलना में यह महत्वपूर्ण संकेतक आज 5 गुना से भी अधिक वृद्धि के साथ 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

पिछली सरकार से तुलना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे और राजमार्गों के बजट में 8 गुना वृद्धि देखी गई है। कृषि और रक्षा बजट में क्रमशः 4 और 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हर क्षेत्र के बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी टैक्स में रिकॉर्ड कटौती के बाद की गई है। उन्होंने बताया कि 2014 में एक करोड़ रुपये कमाने वाले एमएसएमई को अनुमानित टैक्स देना पड़ता था, अब 3 करोड़ रुपये तक की आय वाले एमएसएमई भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 2014 में 50 करोड़ रुपये तक की आय वाले एमएसएमई को 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था, आज यह दर 22 प्रतिशत है। 2014 में कंपनियां 30 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स देती थीं, आज 400 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के लिए यह दर 25 प्रतिशत है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की अनिश्चितताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की वृद्धि और स्थिरता के अपवाद पर भी विचार व्यक्त किए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त वृद्धि देखी गई और भारत कम वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति वाले वैश्विक परिदृश्य में उच्च वृद्धि और कम मुद्रास्फीति दिखा रहा है। उन्होंने महामारी के दौरान भारत की राजकोषीय बुद्धिमता को भी दुनिया के

लिए एक आदर्श बताया। वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत का योगदान निरंतर बढ़ रहा है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक आघातों के बावजूद वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र विकसित भारत के संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। श्री मोदी ने जीवन को आसान बनाने और

जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग 4.0 मानकों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और रोजगार पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री मोदी ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया अभियानों का उदाहरण दिया और बताया कि 8 करोड़ से अधिक लोगों ने नए व्यवसायों की शुरुआत की है।

उन्होंने कहा कि भारत में 1.40 लाख स्टार्टअप हैं जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इस वर्ष के बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के बहुचर्चित पीएम पैकेज का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 4 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि पीएम पैकेज समग्र और व्यापक है। यह अंतिम छोर तक समाधानों से जुड़ा हुआ है।

श्री मोदी ने युवाओं के कौशल और अनुभव को बढ़ाने के लिए शुरू की गई इंटर्नशिप योजना का भी जिक्र किया, जिससे उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ईपीएफओ योगदान में प्रोत्साहन की घोषणा की है।

श्री मोदी ने बजट में विनिर्माण पहलू पर भी चर्चा की। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' और विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नियमों के सरलीकरण के साथ-साथ 14 क्षेत्रों के लिए बहु-उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पार्क, पीएलआई का उल्लेख किया। इस बजट में देश के 100 जिलों के लिए प्लग-एंड-प्ले निवेश-तैयार निवेश पार्कों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि ये 100 शहर विकसित भारत के नए केंद्र बनेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार मौजूदा औद्योगिक गलियारों का भी आधुनिकीकरण करेगी।

एमएसएमई पर जोर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) को सशक्त बनाने के लिए अपनी सरकार के दृष्टिकोण को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया है और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की हैं। श्री मोदी ने कहा कि हम 2014 से लगातार यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं कि एमएसएमई को आवश्यक कार्यशील पूंजी और ऋण मिले, उनकी बाजार पहुंच और संभावनाएं बेहतर हों और उन्हें औपचारिक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कर में कमी और उनके लिए अनुपालन बोझ को कम करना सुनिश्चित किया गया है।

श्री मोदी ने बजट में कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़ा हुआ आवंटन, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, किसानों की भूमि खंडों को नंबर प्रदान करने के लिए भू-आधार कार्ड, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष, महत्वपूर्ण खनिज मिशन और खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों की आगामी नीलामी। उन्होंने कहा कि ये नई घोषणाएं प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेंगी।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, विशेषकर उभरते क्षेत्रों में अवसरों का सृजन हो रहा है। उन्होंने सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में नाम कमाने की जरूरत बताई, ताकि भविष्य में इसकी अहम भूमिका हो। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उन्होंने विशेष रूप से मोबाइल विनिर्माण क्रांति के मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की।

श्री मोदी ने बताया कि कैसे भारत अतीत में आयातक से शीर्ष मोबाइल निर्माता और निर्यातक बन गया है। प्रधानमंत्री ने भारत में ग्रीन जॉब्स सेक्टर के लिए रोडमैप का भी उल्लेख किया, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ई-वाहन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

छोटे परमाणु रिएक्टरों पर किए जा रहे काम का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे न सिर्फ उद्योग को ऊर्जा पहुंच के रूप में लाभ मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र से जुड़ी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को भी नए कारोबारी अवसर मिलेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष श्री संजीव पुरी उपस्थित थे।

मुख्य बातें

- हमारी सरकार अभूतपूर्व गति और पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है
- आज हम विकसित भारत की ओर यात्रा की चर्चा कर रहे हैं; यह सिर्फ भावना के परिवर्तन को ही नहीं अपितु विश्वास में परिवर्तन को भी दर्शाता है
- भारत का विकास और स्थिरता वर्तमान में अनिश्चित दुनिया के मामले में एक अपवाद है
- हम अपने सभी नागरिकों के लिए 'जीवन की सरलता' और 'जीवन की गुणवत्ता' सुनिश्चित कर रहे हैं
- महामारी के बावजूद भारत की राजकोषीय बुद्धिमता विश्व के लिए आदर्श है
- हमारी सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट है, हमारी दिशा में कोई भटकाव नहीं है
- हमारी सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है, हमारे लिए देश और हमारे नागरिकों की आकांक्षाएं सर्वोपरि हैं
- मैं उद्योग और भारत के निजी क्षेत्र को विकसित भारत के निर्माण का एक सशक्त माध्यम मानता हूं ■

प्रधानमंत्री ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन

भारत आज खाद्य अधिशेष वाला देश है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र (एनएएससी) परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) का उद्घाटन किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय "ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स" है। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत और द्वंद को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ कृषि की तरफ तत्काल ध्यान देना है। इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) 65 वर्षों के बाद भारत में हो रहा है। उन्होंने भारत के 120 मिलियन किसानों, 30 मिलियन से अधिक महिला किसानों, 30 मिलियन मछुआरों और 80 मिलियन पशुपालकों की ओर से सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा, "आप उस भूमि पर हैं, जहां 500 मिलियन से अधिक पशुधन हैं। मैं आपका कृषि और पशु-प्रेमी देश भारत में स्वागत करता हूं।"

श्री मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन कृषि और खाद्यान्न को लेकर हमारी मान्यताएं और हमारे अनुभव हैं। उन्होंने भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को दी गई प्राथमिकता पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने खाद्यान्न के औषधीय गुणों के पीछे संपूर्ण विज्ञान के अस्तित्व का उल्लेख किया।

कृषि पाराशर

प्रधानमंत्री ने समृद्ध विरासत पर आधारित कृषि पर लगभग 2000 साल पुराने ग्रंथ 'कृषि पाराशर' का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि हजारों साल पुराने इस दृष्टिकोण की नींव पर विकसित हुई है। श्री मोदी ने भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा की एक मजबूत प्रणाली की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "आईसीएआर खुद 100 से अधिक शोध संस्थानों का दावा करता है।" श्री मोदी ने आगे बताया कि कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं।

भारत में कृषि नियोजन में सभी छह मौसमों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा, "चाहे वह ज़मीन पर खेती हो, हिमालय में, रेगिस्तान में, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में, यह विविधता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और भारत को दुनिया में उम्मीद की किरण दिखाई देती है।"

65 साल पहले भारत में आयोजित कृषि अर्थशास्त्रियों के पिछले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत एक नया स्वतंत्र राष्ट्र था, जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत खाद्य अधिशेष वाला देश है, दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और खाद्यान्न, फल, सब्जियां, कपास, चीनी, चाय और मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

श्री मोदी ने उस समय को याद किया जब भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, जबकि आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रणाली परिवर्तन पर चर्चा के लिए भारत का अनुभव मूल्यवान है और इससे वैश्विक दक्षिण को लाभ मिलना निश्चित है।

उन्होंने 'विश्व बंधु' के रूप में वैश्विक कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने वैश्विक कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण को याद किया और 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य', 'मिशन लाइफ' और 'एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य' सहित विभिन्न मंचों पर भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न मंत्रों का उल्लेख किया।

भारत की आर्थिक नीतियों के केन्द्र में कृषि

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत की आर्थिक नीतियों के केन्द्र में कृषि है। उन्होंने कहा कि भारत के 90 प्रतिशत छोटे किसान, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे

बड़ी ताकत हैं। श्री मोदी ने बताया कि एशिया के कई विकासशील देशों में भी ऐसी ही स्थिति है, जिसके लिए भारत का मॉडल उपयुक्त है।

जलवायु-अनुकूल फसलों से संबंधित अनुसंधान और विकास पर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में किसानों को लगभग उन्नीस सौ नई जलवायु-अनुकूल किस्में सौंपी गई हैं। उन्होंने भारत में चावल की किस्मों का उदाहरण दिया, जिन्हें पारंपरिक किस्मों की तुलना में 25 प्रतिशत कम पानी की आवश्यकता होती है और काले चावल के सुपरफूड के रूप में उभरने का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा, "मणिपुर, असम और मेघालय का काला चावल अपने औषधीय गुणों के कारण पसंदीदा विकल्प है।" उन्होंने कहा कि भारत विश्व समुदाय के साथ इससे संबंधित अपने अनुभव साझा करने के लिए भी उतना ही उत्सुक है।

श्री मोदी ने जल की कमी और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ पोषण संबंधी चुनौतियों की गंभीरता को भी स्वीकार किया। उन्होंने श्री अन्न, मिलेट को एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि यह सुपरफूड 'न्यूनतम पानी और अधिकतम उत्पादन' की गुणवत्ता रखता है। श्री मोदी ने भारत की मोटे अनाज की टोकरी को दुनिया के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की और पिछले वर्ष को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने का उल्लेख किया।

कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल

कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सौर ऊर्जा खेती के कारण किसानों को ऊर्जा प्रदाता बनने, डिजिटल कृषि बाजार यानी ई-नाम, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बात की। उन्होंने पारंपरिक किसानों से लेकर कृषि स्टार्टअप्स, प्राकृतिक खेती से लेकर फार्मस्टे और फार्म-टू-टेबल तक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के औपचारिकीकरण पर भी बात की।

श्री मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 90 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ हो रहा है

भारत में कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के लाभ उठाने पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया, जिसके तहत एक क्लिक पर 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जो किसानों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है और उन्हें डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल से करोड़ों किसानों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

भारत में कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के लाभ उठाने पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया, जिसके तहत एक क्लिक पर 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जो किसानों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है और उन्हें डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है

श्री मोदी ने भूमि के डिजिटलीकरण के लिए एक बड़े अभियान का भी जिक्र किया, जिसके तहत किसानों को उनकी भूमि के लिए एक डिजिटल पहचान संख्या दी जाएगी और खेती में ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां 'ड्रोन दीदियों' को ड्रोन संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इन कदमों से न केवल भारत के किसानों को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी।

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति का उल्लेख किया और विश्वास व्यक्त किया कि अगले पांच दिन दुनिया को टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों से जोड़ने के तरीकों के साक्षी बनेंगे। उन्होंने कहा, "हम एक-दूसरे से सीखेंगे और एक-दूसरे को सिखाएंगे।"

मुख्य बातें

- भारत में 65 वर्ष बाद हुआ सम्मेलन; प्रधानमंत्री ने 120 मिलियन किसानों, 30 मिलियन से अधिक महिला किसानों, 30 मिलियन मछुआरों और 80 मिलियन पशुपालकों की ओर से प्रतिनिधियों का स्वागत किया
- भारतीय कृषि परम्परा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी गई है
- भारत के पास अपनी विरासत आधारित कृषि शिक्षा और अनुसंधान की एक मजबूत प्रणाली है
- एक समय था जब भारत की खाद्य सुरक्षा वैश्विक चिंता का विषय थी, आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है
- भारत 'विश्व बंधु' के रूप में वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है
- टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों के समक्ष चुनौतियों से 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के समग्र दृष्टिकोण से ही निपटा जा सकता है
- छोटे किसान भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं ■

प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की प्रगति की सराहना की

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात शीर्ष 3 में शामिल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात विश्व स्तर पर शीर्ष 3 में पहुंच गया है। श्री मोदी ने इसका श्रेय नवोन्मेषी युवा शक्ति को दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत आने वाले समय में इस गति को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब शीर्ष 3 में शामिल हो गया है। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार का एक समाचार लेख भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत से एप्पल आईफोन के निर्यात में उछाल के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स ने रत्न और आभूषण को पीछे छोड़ते हुए 2024-25 (वित्त वर्ष 25) की अप्रैल-जून तिमाही (क्यू 1) के अंत तक भारत के शीर्ष 10 निर्यातों में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा, "यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की ताकत को हमारी नवोन्मेषी युवा शक्ति ने गति दी है। यह सुधारों और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर हमारे विशेष जोर का भी प्रमाण है। भारत आने वाले समय में इस गति को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है।" ■

प्रधानमंत्री ने असम के चराईदेउ स्थित मैदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की

चराईदेउ स्थित मैदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के चराईदेउ स्थित मैदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किये जाने पर प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है। श्री मोदी ने 26 जुलाई को कहा कि चराईदेउ स्थित मैदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जो पूर्वजों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती है।

उपरोक्त यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के बारे में एक्स पर यूनेस्को की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत के लिए बेहद खुशी और गर्व की बात! चराईदेउ स्थित मैदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जो पूर्वजों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती है। मुझे आशा है कि अधिक संख्या में लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में जानेंगे। प्रसन्नता है कि मैदाम विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं।" ■

प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन के लिए देशवासियों को दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार अगस्त को गैस उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए देशवासियों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि 'विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धि में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि देश ने गैस उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2020-21 में गैस उत्पादन 28.7 बीसीएम था। वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 36.43 बीसीएम कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में गैस उत्पादन 45.3 बीसीएम हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्री के एक्स पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, "देशवासियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। गैस उत्पादन का यह रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।" ■

जीईएम पोर्टल से सार्वजनिक खरीद 9.82 लाख करोड़ रुपये के पार

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीईएम ने 62 लाख से अधिक लेनदेन दर्ज किए। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में लगभग 1000 गुना की वृद्धि को परिलक्षित करता है

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) ने 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) हासिल किया है, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में लगभग 1000 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। 30 जुलाई, 2024 तक जीईएम पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए संचयी जीएमवी इसकी स्थापना के बाद से 9.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जीईएम का सकल व्यापारिक मूल्य 422 करोड़ रुपये का था।

यह जानकारी केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्री जितिन प्रसाद ने नौ अगस्त को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीईएम ने 62 लाख से अधिक लेनदेन दर्ज किए। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में लगभग 1000 गुना की वृद्धि को भी परिलक्षित करता है। शुरुआत से ही जीईएम पोर्टल पर संचयी लेनदेन 30 जुलाई, 2024 तक 2.26 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।

जीईएम पोर्टल पर शुरुआत से ही 1.63 लाख से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसई पंजीकृत किए गए हैं। 30 जुलाई, 2024 तक स्थापना के बाद से महिला एमएसई ने 35,138 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे किए हैं।

शुरुआत से लेकर अब तक जीईएम पोर्टल पर पच्चीस हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। स्टार्ट-अप ने 30 जुलाई, 2024 तक अपनी स्थापना के बाद से जीएमवी में 27,319 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं।

जीईम सहायक

श्री जितिन प्रसाद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 'जीईम सहायक' का उद्देश्य जीईम पोर्टल पर विक्रेताओं और खरीदारों से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल में सहायक नामक प्रमाणित एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों का एक पूल बनाना है तथा विक्रेताओं व खरीदारों दोनों को मदद करने के लिए जीईम सहायक प्लेटफॉर्म पर एक छोर से दूसरे छोर तक (एंड-टू-एंड) सेवाएं प्रदान करना है, जिससे जीईम पोर्टल पर उनकी यात्रा सुविधाजनक हो। ■

वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 2010 की तुलना में 73 प्रतिशत की कमी आई

2013 में 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 2024 में (अप्रैल, 2024 से प्रभावी) 09 राज्यों में केवल 38 जिले रह गई है

वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 2010 के उच्च स्तर की तुलना में 73 प्रतिशत की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप मौतें (सुरक्षा बल+नागरिक) 2010 के सर्वकालिक उच्चतम 1005 से 86 प्रतिशत कम होकर 2023 में 138 हो गई हैं। चालू वर्ष 2024 (30.06.2024 तक) में 2023 की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में वामपंथी उग्रवाद द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं में 32 प्रतिशत और नागरिकों एवं सुरक्षा बल कर्मियों की इसके कारण मौतों में 17 प्रतिशत की तीव्र कमी आई है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने छह अगस्त को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

वामपंथी उग्रवाद हिंसा का भौगोलिक प्रसार भी काफी हद तक सीमित हो गया है। 2013 में 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 2024 में (अप्रैल, 2024 से प्रभावी) 09 राज्यों में केवल 38 जिले रह गई है।

वर्ष 2010 में 96 जिलों के 465 पुलिस स्टेशनों से वर्ष 2023 में 42 जिलों के 171 पुलिस स्टेशनों तक वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2024 (जून, 2024 तक) में 30 जिलों के 89 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट की गई है।

गौरतलब है कि वामपंथी उग्रवाद के खतरे का समग्र रूप से समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 'वामपंथी उग्रवाद का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी। नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी क्रियाकलापों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करने आदि को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। ■

2,30,792 करोड़ रुपये जमा के साथ 52.81 करोड़ पीएम जन-धन खाते खोले गए

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 29.37 करोड़ (55.6%) खाते महिलाओं के हैं और लगभग 35.15 करोड़ (66.6%) खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 19.07.2024 तक 2,30,792 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ कुल 52.81 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं। पीएमजेडीवाई के तहत इनमें से 29.37 करोड़ (55.6%) जन-धन खाते महिलाओं के हैं और लगभग 35.15 करोड़ (66.6%) खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। यह जानकारी पांच अगस्त को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 14.08.2018 से पीएमजेडीवाई का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी वयस्कों को इसके दायरे में लाना रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि पीएमजेडीवाई देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकिंग पहुंच बढ़ाने में सफल रही है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हर परिवार को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, असुरक्षित लोगों को सुरक्षा देना, वित्तपोषण से वंचितों को वित्तपोषित करना तथा वंचित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। 19.07.2024 तक इनका कवरेज इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए कुल 20.48 करोड़ नामांकन किए गए हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 2 लाख रुपये (मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता) और 1 लाख रुपये (स्थायी आंशिक विकलांगता) का एक वर्षीय दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए कुल 45.08 करोड़ नामांकन किए गए हैं।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए कुल 6.71 करोड़ नामांकन किए गए हैं।

ऋण संबंधित योजनाएं

श्री चौधरी ने कहा कि 'वित्तपोषण से वंचित लोगों को वित्तपोषित करने' के उद्देश्य से और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न ऋण संबंधित योजनाएं शुरू की हैं, जिनकी प्रगति इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत 29.93 लाख करोड़ रुपये (12.07.2024 तक) के कुल 48.92 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को गिरवी-मुक्त संस्थागत वित्त प्रदान करना है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 53,609 करोड़ रुपये (15.07.2024 तक) के कुल 2.36 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

7.09.2023 को शुरू की गई **पीएम विश्वकर्मा योजना** का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, बंधक-मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार संपर्क सहायता और डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को राहत प्रदान करना था। इस योजना का उद्देश्य न केवल स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देकर उन्हें सशक्त बनाना है, बल्कि उनके समग्र आर्थिक विकास के लिए भी काम करना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन और इनकी प्रभावशीलता की निगरानी के लिए एक आवधिक समीक्षा तंत्र मौजूद है। ■

देश में वर्ष 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन हुआ

कोयला मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। देश में वर्ष 2023-24 में देश में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 997.828 मिलियन टन (एमटी) अनंतिम रहा। पिछले पांच वर्षों में देश में कोयले के उत्पादन की मात्रा और आयातित कोयले की मात्रा निम्न है:

(आंकड़े मिलियन टन (एमटी) में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
उत्पादन	730.874	716.083	778.210	893.191	997.828
आयात	248.537	215.251	208.627	237.668	261.001

* अनंतिम आंकड़े

936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मिली मंजूरी

राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2013-14 में 0.91 लाख किलोमीटर से करीब 6 गुना बढ़कर अब 1.46 लाख किलोमीटर हो चुकी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दो अगस्त को देशभर में 50,655 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की बुनियाद है और यह नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए हरेक रुपये से देश के सकल घरेलू उत्पाद पर 2.5 से 3 गुना प्रभाव पड़ता है।

देश के समग्र आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार पिछले दस वर्षों से देश में विश्वस्तरीय सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी निवेश कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की लंबाई 2013-14 में 0.91 लाख किलोमीटर से करीब 6 गुना बढ़कर अब 1.46 लाख किलोमीटर हो चुकी है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के आवंटन एवं निर्माण की रफ्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए ठेकों के आवंटन की औसत वार्षिक गति 2004-14 में करीब 4,000 किलोमीटर थी, जो करीब 2.75 गुना बढ़कर 2014-24 में करीब 11,000 किलोमीटर हो चुकी है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्गों का औसत वार्षिक निर्माण भी 2004-14 में करीब 4,000 किलोमीटर से लगभग 2.4 गुना बढ़कर 2014-24 में करीब 9,600 किलोमीटर हो चुका है। निजी निवेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल पूंजी निवेश 2013-14 में 50,000 करोड़ रुपये से 6 गुना बढ़कर 2023-24 में लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इसके अलावा, सरकार ने स्थानीय भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर केंद्रित पहले के परियोजना-आधारित विकास दृष्टिकोण के मुकाबले उपयुक्त मानकों, उपयोगकर्ताओं की सुविधा और लॉजिस्टिक्स दक्षता को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर आधारित राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास का दृष्टिकोण अपनाया है। कॉरिडोर वाले इस दृष्टिकोण के तहत जीएसटीएन और टोल आंकड़ों पर आधारित वैज्ञानिक परिवहन अध्ययन के जरिये 50,000 किलोमीटर के हाई-स्पीड हाईवे कॉरिडोर नेटवर्क की पहचान की गई है, जो 2047 तक भारत को 30 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेगा। ■

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आईटीआर किए गए दाखिल

7.28 करोड़ आईटीआर में से 5.27 करोड़ नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए। इस प्रकार लगभग 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार करदाताओं और कर पेशेवरों द्वारा समय पर अपना अनुपालन किए जाने से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2024 तक दाखिल किए गए आईटीआर का एक नया रिकॉर्ड बना। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 7.28 करोड़ से अधिक रही, जो निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई, 2023 तक दाखिल कुल आईटीआर (6.77 करोड़) से 7.5 प्रतिशत अधिक है।

इस वर्ष बड़ी संख्या में करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है। निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से 5.27 करोड़ नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए हैं, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में 2.01 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। इस प्रकार, लगभग 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, जबकि 28 प्रतिशत करदाता पुरानी कर व्यवस्था में बने हुए हैं।

विभाग को पहली बार दाखिल करने वाले लोगों से 31.07.2024 तक 58.57 लाख आईटीआर भी प्राप्त हुए, जो कर आधार के विस्तार का एक उपयुक्त संकेत है।

उल्लेखनीय है कि करदाताओं को अपना आईटीआर जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सोशल मीडिया पर केंद्रित संपर्क अभियान चलाए गए। इसके साथ ही, विभिन्न मंचों पर अनूठे रचनात्मक अभियान भी चलाए गए। ■

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मिली मंजूरी

शहरी गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे; पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नौ अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दे दी। पीएमएवाई-यू 2.0 पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी I

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास परियोजनाओं में से एक है। 2015 में शुरू की गई इस योजना ने देशभर में करोड़ों परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाओं सहित उनका अपना पक्का आवास प्रदान कर उन्हें नई पहचान दिलाई है। पीएमएवाई-यू के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास निर्माणाधीन हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 15 अगस्त, 2023 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि भारत सरकार आने वाले वर्षों में कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर के स्वामित्व का लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना लाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून, 2024 को पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुसरण में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत एक करोड़ पात्र परिवारों की पक्के आवास की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक नागरिक बेहतर जीवन जी सके।

इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को उनके पहले घर के निर्माण/खरीद के लिए बैंकों/हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी)/प्राथमिक ऋण संस्थानों से लिए गए किफायती आवास ऋण पर क्रेडिट रिस्क गारंटी का लाभ प्रदान करने के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) का कॉर्पस फंड 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी कंपनी (एनसीजीटीसी) को हस्तांतरित किया जाएगा। ■

कैबिनेट ने भारतीय रेल में 8 नई लाइन परियोजनाओं को दी मंजूरी

ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल इन सात राज्यों के 14 जिलों को कवर करने वाली 8 परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नौ अगस्त को तकरीबन 24,657 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत के साथ रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

नई लाइनों के ये प्रस्ताव सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेल को बढ़ी हुई दक्षता और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाएंगी, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के जरिए संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल इन सात राज्यों के 14 जिलों को कवर करने वाली 8 परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 'अजंता' की गुफाओं को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ सकेंगे। ■

जननेता 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी

अटलजी ने भारतीय राजनीति में एक अनूठी और गौरवशाली विरासत छोड़ी है। उन्होंने वास्तव में भारत की भावना का प्रतिनिधित्व किया, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं ने राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को आकार दिया है। वह राजनीति में आपातकाल और तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करने में भी सबसे आगे रहे। उनका राष्ट्रवाद लोकतांत्रिक भावना से ओत-प्रोत था, जिसमें भारतीय समाज की विविधताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सरोकारों के विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति विकसित करने की परंपरा के माध्यम से संबोधित किया गया है। अपने लंबे संसदीय जीवन में वे विपक्ष में रहते हुए भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे।

राष्ट्र को परेशान करनेवाली विभिन्न समस्याओं पर उनकी पकड़ के कारण ही उन्होंने राष्ट्रीय लोकाचार और मूल्य आधारित राजनीति के भीतर सभी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया। देश की मिट्टी से जुड़े वह एक ऐसे नेता थे, जो अपनी राजनीतिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे, इस बात का उनके राजनीतिक विरोधी भी सम्मान करते थे। राष्ट्र को उन पर इतना विश्वास था कि संकट के समय उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी उनकी सलाह ली थी। 'मां भारती' के सच्चे सपूत के रूप में उन्होंने कई मौकों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना पसंद किया और राष्ट्रीय हितों की वेदी पर पार्टी के हितों का त्याग करने के विकल्प को भी चुना। जब आपातकाल घोषित किया गया, तो जनसंघ का विलय व्यापक राष्ट्रीय हित में जनता पार्टी में कर दिया गया। सिद्धांतों और विचारधारा पर एक अडिग नेता के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ जनता पार्टी से बाहर आए। उनका सैद्धांतिक और मूल्य आधारित राजनीति पर अटूट विश्वास था।

पूर्व रियासत ग्वालियर (अब मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा) में 25 दिसंबर, 1924 को एक सामान्य स्कूल शिक्षक के परिवार में जन्मे श्री वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन

राष्ट्र को उन पर इतना विश्वास था कि संकट के समय उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी उनकी सलाह ली थी। 'मां भारती' के सच्चे सपूत के रूप में उन्होंने कई मौकों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना पसंद किया और राष्ट्रीय हितों की वेदी पर पार्टी के हितों का त्याग करने के विकल्प को भी चुना

में उदय उनके राजनीतिक कौशल और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। दशकों बाद वह एक ऐसे नेता के रूप में उभरे, जिन्हें उनके उदार विश्वदृष्टि और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए जाना गया।

एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी जादुई शैली से जनता को मंत्रमुग्ध किया। राष्ट्र उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था और यह सपना देश में लोगों के बढ़ते समर्थन के साथ साकार भी हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय सफलता के साथ हर मोर्चे पर देश का नेतृत्व किया। भारत एक शांतिपूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में उभरा, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने पथ पर चलता रहा। एक सच्चे 'अटल' के रूप में वे कभी दबाव में नहीं झुके, बल्कि यह उनके लिए वैश्विक स्तर पर भारत की आंतरिक ताकत को साबित करने का एक अवसर था। उन्होंने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हुए और भारत को विभिन्न मोर्चों पर 'आत्मनिर्भर' बनाते हुए सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखी। जैसाकि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, उन्होंने समय के कैनवास पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग उभरते हुए नए भारत के लिए मार्गदर्शक बन गया।

अटलजी ने पीढ़ी-दर-पीढ़ी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की गहन भावना के साथ सार्वजनिक जीवन में योगदान देने के लिए सभी को प्रेरित किया है। भारतीय राजनीति में विकल्प देने के उद्देश्य से शुरू हुए राजनीतिक आंदोलन की परिणति उनके रूप में हुई, क्योंकि वे भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। यह उनके नेतृत्व में बनाया गया एक इतिहास था और देश के लाखों लोगों द्वारा पोषित एक विरासत थी। एक सच्चे राजनेता, लोकतंत्रवादी, आम सहमति बनानेवाले और सबसे बढ़कर वह राजनीति में एक सज्जन पुरुष के रूप में जाने जाते रहे। अटलजी का स्वर्गवास 16 अगस्त, 2018 को 93 वर्ष की आयु में हो गया।

'कमल संदेश' अटलजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ■

अनुच्छेद 370 और 35(ए) के निरस्तीकरण के 5 वर्ष

यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त करने के संसद के 5 वर्ष पुराने निर्णय को याद करते हुए इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई है।

श्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज हमारे देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण के 5 साल पूरे हो रहे हैं, जब भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने का फैसला किया था। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। इसका मतलब था कि भारत के संविधान को इन जगहों पर अक्षरशः लागू किया जाएगा, जो महान संविधान निर्माताओं की दृष्टि के अनुरूप है।"

उन्होंने कहा कि निरस्तीकरण के साथ महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, जनजातीय और वंचित समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर आए, जो विकास के लाभ से वंचित थे। साथ ही, इसने दशकों से जम्मू-कश्मीर में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर रखना भी सुनिश्चित किया है। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और शांति के लिए धारा 370 का निरस्तीकरण एक निर्णायक कदम है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से धारा 370 और 35 (ए) हटाये जाने की 5वीं वर्षगांठ पर कहा कि यह कदम इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन अनुच्छेदों को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है।

श्री नड्डा ने एक्स पर लिखा, "आज जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण की 5वीं वर्षगांठ है - अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त किया गया। पांच साल पहले, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन अनुच्छेदों को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मुख्यधारा में लाने का साहसिक कदम उठाया था।

इस ऐतिहासिक निर्णय से पहले अनुच्छेद 370 और 35 (ए) ने क्षेत्र के लोगों को प्रगति और विकास से वंचित रखा था, जो हमारे व्यापक विकास के मार्ग में बाधा बन रहे थे। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना, क्षेत्र में सर्वांगीण विकास और शांति लाने के लिए एक निर्णायक कदम था।

तब से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने परिवर्तनकारी विकास और प्रगति देखी है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने युवा के लिए लाखों अवसरों के द्वार खोले हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। इस कदम ने वास्तव में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को निरंतर विकास एवं समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त किया है।"

अनुच्छेद 370 और 35(ए) के निरस्तीकरण ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पांच अगस्त को कहा कि अनुच्छेद 370 और 35(ए) के निरस्त करने के परिवर्तनकारी निर्णय ने वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35(ए) को निरस्त किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के आज पांच साल पूरे हो गए हैं। इस परिवर्तनकारी निर्णय ने वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाया है, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के प्रयासों को सफलता मिली है। श्री शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण को दोहराते हैं। ■

भारतीय जनसंघ ही क्यों?

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

गतांक से...

अतः हमने एक मूलभूत प्रश्न उठाया है और यह घोषणा की है कि पाकिस्तान आज जो कुछ कर रहा है वह विभाजन की आधारभूत शर्त को पूर्णतः भंग करता है। इसलिए यह समझाना जाना चाहिए कि विभाजन का आधार नष्ट हो गया। गांधीजी ने भी कहा था कि यदि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान न कर सके तो उसका दायित्व भारत को संभालना चाहिए। हम तुरन्त ही युद्ध घोषणा की बात नहीं कर रहे हैं। हम यह मानते हैं कि हमारी ही सरकार की दुर्बल तथा अस्थिर नीति के कारण ही पाकिस्तान सरकार को बेरोक-टोक आगे बढ़ने का साहस मिला है। अतः हमारी मांग है कि भारत सरकार अपनी पाकिस्तान विषयक नीति में आमूल परिवर्तन करे और पाकिस्तान के विरुद्ध प्रभावी प्रतिबन्ध लगाए। विभाजन के शिकार लाखों व्यक्तियों के मान-सम्मान, जीवन तथा सम्पत्ति की हानि तथा स्त्रियों पर हुए अत्याचार के अतिरिक्त हमारी नपुंसकता और हृदयहीनता ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा को भारी धक्का पहुंचाया है। यह कोई प्रांत विशेष का प्रश्न नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है और दोनों राज्यों के बीच सुलझाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जनमत जाग्रत करना होगा जो समय रहते सही कदम उठाने के लिए सरकार को विवश करे। पाकिस्तान हमारे मुंह पर तमाचे पर तमाचे लगाता जा रहा है, वह फिर हिन्दुओं की सुरक्षा हो अथवा व्यापार और लेन-देन, सीमाओं की अभंगनियता या कश्मीर। दुर्भाग्य का विषय है कि पाकिस्तान की दृष्टि में हमारा मूल्य इतना गिर गया है कि वह मौके-बमौके हमारा अपमान करने का साहस करे और हमारी सरकार कोई भी प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ, असहाय दर्शक बनी रहे। इसके साथ ही भारत में पंचमार्गियों की कार्यवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारी स्वतंत्रता क्षणभंगुर होगी और हम संकट के गहरे गर्त में गिर जाएंगे।

पुनर्वास

राष्ट्रीय महत्व का अन्य विषय पुनर्वास का है। हम लोगों ने मांग की है कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए निर्वासितों के

दुर्भाग्य का विषय है कि पाकिस्तान की दृष्टि में हमारा मूल्य इतना गिर गया है कि वह मौके-बमौके हमारा अपमान करने का साहस करे और हमारी सरकार कोई भी प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ, असहाय दर्शक बनी रहे। इसके साथ ही भारत में पंचमार्गियों की कार्यवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमारी स्वतंत्रता क्षणभंगुर होगी और हम संकट के गहरे गर्त में गिर जाएंगे

संबंध में अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी जांच करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की नियुक्ति की जाय। पश्चिमी पाकिस्तान के निर्वासितों द्वारा वहां छोड़ी हुई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति का प्रश्न कुछ दिनों से सरकार के विचाराधीन है। इसके न्यायपूर्ण हल में बहुत विलम्ब हो गया है। इसी प्रकार निर्वासितों को दिए गए ऋण की वापसी का प्रश्न भी भारी कठिनाई उपस्थित कर रहा है। यह भी दुःख का विषय है कि जम्मू और कश्मीर से निर्वासित हजारों बन्धु भारत में रह रहे हों और उन्हें अपने ही प्रदेश में नहीं बसाया गया हो। लगभग पांच हजार हिन्दू तथा सिख महिलाएं पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा अपहृत हैं, किन्तु उनके उद्धार का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया। ये प्रश्न किसी वर्ग विशेष के नहीं, अपितु इनके हल का दायित्व भारत सरकार और भारत की सम्पूर्ण जनता पर है। भारत की स्वतंत्रता के लिए लाखों देशभक्त, स्त्री और पुरुषों का बलिदान हुआ तथा इसी हेतु वे अमानुषिक अत्याचार के शिकार बने। यदि हम उनके और उनकी सन्तान के साथ न्याय नहीं कर सकते तो हम महान पाप के भागी होंगे, जिसका फल हमें और हमारी सन्तति को भोगना पड़ेगा।

सुसंगठित राष्ट्रजीवन

आज विश्व एक संकट और तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। स्वाभाविक ही हम भारत में एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। किन्तु हमारा विश्वास है कि अपना घर सुधारे बिना, तथा विभाजन से बुरी तरह झकझोरी हुई अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ठीक किये बिना, हम अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में कोई सहयोग नहीं दे सकते। सुदृढ़ राष्ट्रीयता के आधार पर ही अन्तरराष्ट्रीयता पनपती है। अतः हमें अपने आन्तरिक मोर्चे को सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र का बल सेना या शस्त्रों में नहीं, बल्कि उसकी जनता में है। यदि जन संतुष्ट है, संयुक्त है, दृढ़ संकल्प हैं, अथवा राष्ट्रनिर्माण के लिए बलिदान तथा कष्ट सहन करने को तत्पर है, तो विश्व की कोई भी शक्ति ऐसे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। लगभग एक हजार वर्ष के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। राजनीतिक दलों में कैसे भी मतभेद हों, लोगों में कैसी भी आशा

शेष पृष्ठ १५ पर...

भारतीय कृषि का अमृतकाल

शिवराज सिंह चौहान

बीते 10 वर्षों में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने का है

कृषि विकास और किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्न के माध्यम से हमारे जीवन संचालन के सूत्रधार अन्नदाता के जीवन में सुख-समृद्धि लाना हमारा संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। किसान की आय बढ़ाने के लिए हमने छह सूत्रीय रणनीति बनाई है।

उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा में राहत की उचित राशि दिलाना, कृषि का विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसके अहम पहलू हैं। उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सबसे जरूरी हैं अच्छे बीज, जो कम पानी और विपरीत मौसम में भी बेहतर उत्पादन में सक्षम हो सकें। ऐसे बीजों की 109 नई किस्मों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र और किसानों को समर्पित किया है।

बीते 10 वर्षों में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने का है। वर्तमान में विज्ञान से ही किसानों का कल्याण संभव है। मुझे अपने कृषि विज्ञानियों पर गर्व है जो जलवायु अनुकूल किस्में तैयार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि में किए जा रहे नवाचारों से कृषि एवं किसान कल्याण सुनिश्चित होगा।

किसान होने के नाते मैं भलीभांति समझता हूं कि बढ़िया उत्पादन के लिए अच्छे बीज कितने आवश्यक हैं। अगर बीज उन्नत और मिट्टी एवं मौसम की प्रकृति के अनुकूल होंगे तो उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मोदी जी ने यह समझा और व्यापक विजन के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शित किया। विविधता भारतीय कृषि की विशेषता है।

यहां कुछ दूरी के अंतराल पर ही खेती का मिजाज बदल जाता है। जैसे मैदानी खेती अलग है तो पहाड़ों की खेती अलग। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों की 109 नई किस्में जारी की गई हैं। इनमें खेती की 69 किस्में और बागवानी की 40 किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई हैं। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने और श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है।

हमारा संकल्प है कि किसान के परिश्रम का उचित मूल्यांकन हो और उन्हें फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भारत की चिंता भी रही है कि मानव शरीर और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन हो।

आज भारत नई हरित क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता तथा ईंधनदाता भी बन रहे हैं। मोदी जी के प्रयासों से खेती के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय खेती, फूलों-फलों की खेती सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकता में कृषि और किसान रहे ही नहीं, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27 हजार 663 करोड़ रुपये था जो 2024-25 में बढ़कर 1 लाख 32 हजार 470 करोड़

रुपये हो गया है। यह बजट सिर्फ कृषि विभाग का है। कृषि से संबद्ध क्षेत्रों और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अलग बजट है। मोदी सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है।

यूरिया पर सरकार किसानों को करीब 2,100 रुपये सब्सिडी जबकि डीएपी के एक बैग पर 1083 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान स्वावलंबी और सशक्त हुआ है। फसलों के नुकसान पर भी फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है।

मोदी सरकार में किसान को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लिया, जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए। उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। इसी कड़ी में एक लाख करोड़ रुपये की एग्री इन्फ्रा फंड के जरिये कृषि से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है।

पूरे देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसान और विज्ञान को जोड़ रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिये टेक्नोलाजी से दूरदराज की हमारी माताओं-बहनों को भी जोड़ा जा रहा है। कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने के पहले चरण में अब तक 35 हजार कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मोदी जी का विजन है कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में भी रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 100 निर्यात केंद्रित बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 1500 से अधिक मंडियों का एकीकरण किया जाएगा।

साथ ही 6,800 करोड़ रुपये की लागत से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने की भी तैयारी है। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल और अन्य उपज के लिए नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार ने यह संकल्प भी लिया है कि दलहन फसलों में तुअर, उड़द और मसूर की पूरी खरीद एमएसपी पर की जाएगी।

यजुर्वेद में उल्लिखित है 'अन्नानां पतये नमः क्षेत्राणां पतये नमः' अर्थात् अन्न के स्वामी और खेतों के स्वामी अन्नदाताओं को नमन। कृषि पराशर में भी उल्लेख है— अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है एवं अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। किसानों के बिना इस देश का अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी किसानों को प्रणाम किया गया है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसका आत्मा। हमारे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घकालिक विजन तथा सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, समावेशी और समग्र विकास वाले सोच के साथ भारत एवं भारतीय कृषि निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई-बहन आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और समृद्ध संपन्न होने के साथ-साथ देश के अन्न भंडार भरते रहेंगे। ■

(लेखक केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं)

पृष्ठ १३ का शेष भाग...

और आशंकाएं हों, किन्तु हमें इतिहास का पाठ पढ़ाना होगा तथा फूट का शिकार न बनकर अपने विनाश को रोकना होगा। राष्ट्रीय चरित्र की परीक्षा राष्ट्र के संकटकाल में ही होती है। ऐसे समय में अपने सब आन्तरिक मामलों को भुलाकर संघटित राष्ट्र के नाते, जिनका एकमेव उद्देश्य राष्ट्रनिर्माण और मातृभूमि की अखण्डता की रक्षा है, खड़ा होना सीखना होगा।

विश्वशान्ति की आवश्यकता

यह अन्तरराष्ट्रीय राजनीति का दुःखद विषय है कि विश्व दो शक्तिशाली गुटों में बंट गया है और प्रत्येक यह सोचता है कि जो उसके साथ नहीं है वह उसके शत्रु के साथ होगा। हम समझ नहीं पाते कि हम एक विचारधाराओं के संघर्ष में से गुजर रहे हैं अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति और सत्ता हथियाने के युग में से। 'जीओ और जीने दो' का सिद्धान्त भारत ने अनादिकाल से स्वीकार किया है। सब लोगों के शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए दुनिया काफी बड़ी है। प्रत्येक देश को अधिकार है कि वह अपनी जनता की इच्छा के अनुसार उसके प्रतिनिधियों द्वारा निर्णीत विचारधारा, अर्थनीति और समाजदर्शन का अपने ढंग से विकास करे। कठिनाई तो तब उपस्थित होती है, जब एक देश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करता है और अपनी बद्धमूल धारणाओं के प्रचार का अथवा अपने प्रभाव के विस्तार का प्रयत्न करता है। हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप के सभी प्रयत्नों का हम विरोध करेंगे। यह संकट और भी गंभीर हो जाता है जबकि यह हस्तक्षेप खुले रूप से न होकर अपने ही देशवासियों की कार्यवाहियों के रूप में होता है। ये लोग एक प्रकार से विदेशियों के एजेंट ही हैं, जो सदैव उनके ही हितों की चिन्ता करते हैं। हमारा जनतंत्र तथा धर्म राज्य पर विश्वास है। किसी भी प्रकार का एकाधिपत्य अभारतीय हैं और इस देश में किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। हमारी किसी भी देश के प्रति दुर्भावनाएं नहीं हैं और हम मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस जैसे भिन्न देशों को भी बहुत से क्षेत्रों में सफलता मिली है।

अपनी परम्पराओं के अनुरूप तथा भविष्य के विकास की भारी संभावनाओं के आधार पर भारत विश्व में शान्ति और सद्भाव का वातावरण निर्माण करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक विकृत कल्पना तथा गंभीर आर्थिक स्थिति भारत की जनशक्ति और प्राकृतिक साधनों के विकास में बाधा बनी हुई है। जब तक भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुदृढ़ नींव पर खड़ा होकर बदले हुए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप समता, नैतिकता और प्रगति की दीपशिखा लेकर आगे नहीं बढ़ता, तब तक उसका भविष्य प्रकाशमान नहीं होगा। सभी देशवासियों के सहयोग और सद्भाव के बल पर जनसंघ राष्ट्रनिर्माण के इस महान कार्य में सफल हो, यही मेरी कामना है। ■

।। वन्दे मातरम् ।।

समाप्त

हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई 'कर व्यवस्था' से मध्यम वर्ग को लाभ होगा: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 7 अगस्त को लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर दिया। अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार ने वास्तव में कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शिता एवं अनुपालनों को सरल बनाया है और हमारी सरकार द्वारा तैयार की गई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। हम अपने सुधी पाठकों के लिए इस भाषण का सारांश यहां प्रकाशित कर रहे हैं:

माननीय प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण इस देश में एक सरल, कुशल, निष्पक्ष और प्रौद्योगिकी संचालित कराधान व्यवस्था स्थापित करना रहा है। इसलिए कराधान संबंधी दृष्टिकोण करदाताओं पर बोझ को कम करने का रहा है। हमने वास्तव में अधिक पारदर्शिता और अनुपालन में सुगमता के साथ कराधान व्यवस्था को सरल बनाया है। कुछ माननीय सदस्यों ने मध्यम वर्ग पर कर के बोझ के बारे में बोला है। मेरा मानना है कि इस सरकार द्वारा बनाई गई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग को लाभ होगा। वर्ष 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया था। इस सरकार ने नई कर व्यवस्था में स्लैब में फिर से संशोधन किया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। पिछले दो वर्षों में मध्यम वर्ग को काफी राहत दी गई है। हम फेसलेस सिस्टम लाए हैं, जो करदाता के अनुकूल है और इससे करदाता में विश्वास पैदा हुआ है। 'विवाद से विश्वास' योजना की मदद से लंबित मुकदमेबाजी और मांगों को सुलझा लिया गया है और विस्तृत श्रेणियों के करदाताओं को राहत दी गई है। स्टार्ट-अप्स के लिए एंजेल टैक्स हटाना बड़ी राहत लेकर आया है। संप्रग सरकार ने इस कर को वर्ष 2012 में लागू किया था और अब वे विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष के नेता ने इसे शोषणकारी कर कहा था। हमने इस पर काम किया है, ताकि इस एंजेल टैक्स की वजह से बोझ छोटे व्यवसायों पर न पड़े। अंततः हमने अब इसे हटा दिया है।

वर्ष 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया था। इस सरकार ने नई कर व्यवस्था में स्लैब में फिर से संशोधन किया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। पिछले दो वर्षों में मध्यम वर्ग को काफी राहत दी गई है। हम फेसलेस सिस्टम लाए हैं, जो करदाता के अनुकूल है और इससे करदाता में विश्वास पैदा हुआ है

सीमा शुल्क के मामले में हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, प्रक्रियाओं को सरल एवं तेज बनाने और लॉजिस्टिक्स लागत एवं अनुपालन लागत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे निश्चित रूप से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इस बजट में सूचीबद्ध मदों में से कई मदों पर सीमा शुल्क को कम करने का उद्देश्य कच्चे माल और आदानों की कीमतों को कम करना था, इस प्रकार घरेलू उत्पादन को और अधिक लागत प्रभावी बनाना था। व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमने इस वित्त विधेयक में चमड़ा और वस्त्र क्षेत्रों जैसे श्रम प्रधान उद्योगों के लिए कतिपय आदानों पर दरों में कटौती का प्रस्ताव किया है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और शुल्क व्युत्क्रम संबंधी मुद्दों का समाधान होगा जो वस्त्र क्षेत्रों में प्रचलित हैं।

हमने 27 महत्वपूर्ण खनिजों, जो इस देश की सामरिक स्वायत्तता के लिए आवश्यक हैं और बहुमूल्य धातुओं, सोने और चांदी पर शुल्क दरों को कम कर दिया है, क्योंकि भारत हीरों को तराशने और पालिश करने के सबसे बड़े केन्द्रों में से एक है और यह बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करता है। जलकृषि क्षेत्र और समुद्री उद्योग के लिए कतिपय आदानों पर शुल्क दर में कटौती भी की गई है, ताकि हम और अधिक समुद्री उत्पादों, विशेषकर श्रिम्प का निर्यात कर सके। मैंने यह भी घोषणा की है कि अगले छह महीनों के दौरान दर ढांचे की व्यापक समीक्षा

की जाएगी और आशा है कि उस प्रक्रिया के अंत में हमारे पास समग्र रूप से हमारे देश के लिए अधिक सरलीकृत कर ढांचा होगा।

मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि करदाताओं की सुविधा के लिए चार बड़े कदम उठाए गए हैं। यदि कोई आयकर दाता अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने पोर्टल पर जाता है, तो सत्यापित तीसरे पक्ष की जानकारी के आधार पर पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न के द्वारा आय रिपोर्टिंग को तेज और आसान बना दिया गया है। दूसरी बात यह है कि मूल्यांकन और अपील की फेसलेस प्रणाली ने आईटी से संबंधित प्रमुख प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है और मानव इंटरफेस को कम कर दिया है। तीसरा, अब रिफंड कई महीनों के विपरीत कुछ दिनों के भीतर जारी किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई, 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए और पहली बार आयकर दाखिल करने वालों से 58.57 लाख आयकर रिटर्न प्राप्त हुए, जो करदाताओं की संख्या बढ़ने का संकेत देते हैं, जिसके लिए हमने लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मुकदमा तंत्र भी एक ऐसी चीज है जिस पर हमने काफी ध्यान दिया है। कर निर्धारण के मामले को फिर से खोलना और पुनर्मूल्यांकन करना सरल किया गया है। मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूं कि कर निर्धारण के बाद मामले को केवल पांच साल तक खोला जा सकता है, लेकिन चौथे और पांचवें वर्ष के लिए, केवल तभी, जब अघोषित आय 50 लाख रुपये से अधिक हो। तलाशी के मामलों में कर निर्धारण की अवधि अब दस वर्ष से घटाकर केवल छह वर्ष कर दी गई है। हम सभी लंबित अपीलों के निपटारे के लिए विवाद से विश्वास योजना लाए हैं। इसके अलावा, कर न्यायाधिकरणों या उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई है। इससे मुकदमेबाजी कम होगी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

निर्धारण के मामले को फिर से खोलना और पुनर्मूल्यांकन करना सरल किया गया है। मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूं कि कर निर्धारण के बाद मामले को केवल पांच साल तक खोला जा सकता है, लेकिन चौथे और पांचवें वर्ष के लिए, केवल तभी, जब अघोषित आय 50 लाख रुपये से अधिक हो। तलाशी के मामलों में कर निर्धारण की अवधि अब दस वर्ष से घटाकर केवल छह वर्ष कर दी गई है

टीडीएस दरों के यौक्तिकीकरण के संबंध में हमने इस बजट में टीडीएस दरों को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने, कोई अलग दर नहीं और धारा 194 एफ को समाप्त करने, जहां टीडीएस दर 20 प्रतिशत है, का प्रस्ताव किया है। इससे छोटे व्यवसाय के लिए नकदी प्रवाह के मुद्दों में सुधार होगा। हमने टीडीएस के देर से भुगतान को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, अगर यह टीडीएस स्टेटमेंट दाखिल करने की समय सीमा से पहले किया जाता है। हमारे कर प्रस्तावों का उद्देश्य विकास को प्रेरित करना, रोजगार पैदा करना और निवेश लाना है। पोत परिवहन कंपनियों और खनन कंपनियों के लिए कुछ कदम उठाए गए है। अलग-अलग सांसदों ने 'मिडिल क्लास पर टैक्स बोझ विषय पर बात की है। मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि यह नैरेटिव कि कॉर्पोरेट कर व्यक्तिगत करों की तुलना में कम हैं, ठीक नहीं है। यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं केवल इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूं कि हमने लंबित अपीलों को निबटारे के लिए पिछले दो वर्षों में नए तंत्र बनाए हैं। कई सदस्यों द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि आयकर कटौती को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए मध्यम वर्ग घाटे में है। मैं केवल इस बात पर प्रकाश डालना चाहती हूं कि हमने जो नई कर व्यवस्था लागू की है वह सरल है, दरों में कम है। यह करदाता को लचीलापन भी देता है कि वह छूट के अभाव में अपना पैसा कहा रखना चाहता है, लेकिन पुरानी व्यवस्था को भंग नहीं किया गया है। यह अभी भी जारी है और अभी भी लोगों के लाभ के लिए उपलब्ध है। नई कर व्यवस्था वास्तव में लोगों को यह देखने में मदद कर रही है कि वे कम भुगतान कर रहे हैं, वे सरल प्रणाली के साथ लाभान्वित हो रहे हैं। मध्यम वर्ग को नुकसान हो रहा है यह सही तर्क नहीं है।

फिनटेक विकास के कारण लोगों में अधिक जागरूकता आयी है और निवेश में आसानी हो रही है। म्यूचुअल फंड में निवेश भी काफी बढ़ा है। माननीय सदस्यों के एक समूह की चिंता पूंजीगत लाभ कर के संबंध में थी कि यह अधिक है और यह कि इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। पूंजीगत लाभ के संबंध में बजटीय प्रस्ताव का तर्क यह है कि इसे मानकीकृत और सरलीकृत किया जाना चाहिए और सभी परिसंपत्ति वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि गणना, फाइलिंग और रिकार्ड रखने में आसानी हो। वर्तमान संशोधन जो हम ला रहे हैं वह 23 जुलाई, 2024 से पहले व्यक्तियों और एचयूएफ द्वारा अधिग्रहित भूमि और भवन संपत्ति के लिए है और यह निर्धारित करता है कि दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में, भूमि या भवन या दोनों, किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा जिसे 23 जुलाई, 2024 से पहले अधिग्रहित किया गया है, करदाता नई योजना के तहत, जो इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत है और पुरानी योजना में इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत है, अपने करों की

शेष पृष्ठ १९ पर...

यह विधेयक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना संवैधानिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है: किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया और विश्वास व्यक्त किया कि विधेयक के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक संवैधानिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है और संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के तहत गारंटीकृत धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू के संबोधन का संपादित पाठ निम्न है:

मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, बल्कि यकीन है कि इस बिल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद इस सदन के जितने सदस्य हैं, सब इस बिल का समर्थन जरूर करेंगे। इस विधेयक में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जो भी प्रावधान हैं, उसके तहत किसी भी रिलीजियस बॉडी को जो फ्रीडम प्राप्त है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया है और न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और मुसलमान समाज के पिछड़े लोगों को सुअवसर देने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। वर्ष 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस उद्देश्य के लिए यह एक्ट लाया गया था, वह पूरा नहीं हो रहा था। इसमें कई गलतियां पाई गई हैं। उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

वर्ष 1976 वक्फ इक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि सारा वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों के कब्जे में चला गया है, उसको डिसिप्लिन करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट की दूसरी रेकमेडेशन है कि लिटिगेशंस और आपस में मतभेद इतने ज्यादा हैं कि उनको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम का गठन होना चाहिए। यह उस समय की सिफारिशें थीं। उसमें तीसरा पॉइंट ऑडिट एंड एकाउंट्स के बारे में कहा गया है। वक्फ बोर्ड में ऑडिट और एकाउंट्स का तरीका समुचित नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए। यह उस समय की रिपोर्ट में कहा गया है। आखिरी में यह वक्फ-अलल-औलाद की श्रेणी में सुधार की सिफारिश करता है। बच्चों के लिए हम जो वक्फ देते हैं, उसमें सुधार लाना चाहिए।

> **हम मुसलमान समुदाय को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, खासकर गरीब मुसलमान महिलाएं, जो बैकवर्ड हैं, उनके लिए यह कर रहे हैं**

कुल 8 लाख 72 हजार 320 वक्फ संपत्तियां हैं। हमारा जो वामसी (डब्ल्यूएएमएसआई) पोर्टल है, उससे पूरा निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू, सच्चर कमेटी ने जो कहा है, उससे कहीं गुना अधिक होने की संभावना है। समिति की सिफारिश में कहा गया कि मौजूदा वक्फ बोर्ड को ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में दो महिलाएं होनी चाहिए, यह भी सच्चर कमेटी की सिफारिश है। सच्चर कमेटी ने सीधा-सीधा यह कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दी जानी चाहिए। जेपीसी में सीधा-सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से विद्यमान नहीं है। वहां कार्यबल बिल्कुल अप्रभावी है, असक्षम है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। देश भर में मौजूदा जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उनका फिर से सर्वेक्षण होना चाहिए। गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड के अंदर भी चीजें, चाहे वह विधिक मामले हों या कुछ और, उसके लिए विशेषज्ञ वकीली आदि को बोर्ड में लाने की जरूरत है, ताकि वह ज्यादा चुस्त-दुरूस्त हो सकें। पूरे वक्फ बोर्ड का कम्प्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकार्ड में होना चाहिए।

हमारे देश के अन्दर कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकता है। संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं हो सकता है। इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला, चाहे वह कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन या कोई भी हो, यह इस सदन का दायित्व है कि उसे न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है, तो उसको पूरा करना चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से हम लॉ ऑफ लिमिटेशन को हटा रहे हैं। वक्फ एक्ट, 1995 ने लॉ-ऑफ-लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर

दिया था। एकतरफा आवाज उठाकर, पूरे मुसलमान के नाम से कुछ लोग कुछ चंद लोगों की आवाज यहां आज इस सदन में बुलन्द कर रहे हैं। जहां तक विचार-विमर्श की बात आती है, तो हमने कई स्तर पर विचार-विमर्श किया है। हम लोगों ने देश भर में आधिकारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ और व्यक्तिगत स्तर भी पर बहुत व्यापक विचार-विमर्श किया है। हमने 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ और उनके और भी आधिकारिक प्रतिनिधियों से बात की है। वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने मुझसे आकर कहा है कि देश में जितने स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, सब पर माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है।

सरकार वर्ष 2024 में यह वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल अचानक नहीं लेकर आई है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज यह बिल आपके सामने में पेश कर रहा हूं। इसमें अलग-अलग समुदाय जैसे कि अहमदियाज, बोडराज, पसमांदाज, आगाखानीज, वुमेन रिप्रेजेन्टेटिव्स और जितने भी पिछड़े मुसलमान हैं, इन सबके सहित 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओज और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रजेन्टेटिव्स से बात की है। इस सम्बन्ध में जनरल पब्लिक और आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई। स्टेट वक्फ बोर्ड को इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए। इस बिल में हमने एक दूसरा प्रावधान रखा है। जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं, इसमे एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेम्बर होगा। आज वक्फ बोर्ड का टोटल 12,792 केसेस पंडिग हैं। 19,207 केसस ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पर न्याय मिलना चाहिए। इसलिए, बिल में प्रावधान किया गया है कि जो भी फाइलिंग होती है, उसकी अपील 90 डेज के अंदर होनी चाहिए और डिस्पोजल ऑफ दी केसेस छह महीने के अंदर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में टेक्नोलॉजिक इंडक्शन अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड को साइंटिफिक तरीके से बहुत ही एफिसिएंटली और ट्रांसपेरेंटली चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। अब जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड होगा, इसने महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है। इसमें भोराज, अगाकानीज़ और बेकवर्ड क्लासेज को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया है। हमने बच्चों और महिलाओं का काफी ध्यान रखा है। एक्ट पास होने के बाद कोई मुसलमान बच्चा या महिला इंसाफ मिलने से वंचित रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए।

हमने इसके लिए ठोस प्रावधान किए हैं। वक्फ प्रापर्टी की प्रोसीड्स और आय सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए खर्च होगी। हम मुसलमान समुदाय को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, खासकर गरीब मुसलमान महिलाएं, जो बैकवर्ड हैं, उनके लिए यह कर रहे हैं। साथ ही, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और वक्फ (संसोधन) विधेयक, 2024 को उसमें भेजा जाए। ■

पृष्ठ 27 का शेष भाग...

गणना कर सकता है और ऐसे कर का भुगतान कर सकता है जो दोनों में से कम है। रोलओवर प्रावधान भी मौजूद है यदि पूंजीगत लाभ राशि एक या दूसरी संपत्ति में भी निवेश की जाती है। आयकर अधिनियम के 54 ईसी के तहत अधिसूचित उन बॉन्डों या वस्तुओं में सालाना 50 लाख रुपये तक के निवेश का प्रावधान अब भी मौजूद है और यह मध्यम वर्ग को लाभान्वित करने के लिए है। कई सदस्यों ने हमें जीएसटी के संबंध में सुझाव दिए हैं, जिन पर निश्चित रूप से में परिषद् में चर्चा करूंगी क्योंकि अंतिम निर्णय परिषद् पर ही निर्भर है। कई वस्तुओं पर जीएसटी के संबंध में सुझाव आ रहे हैं। 2024-25 के वर्तमान बजट में सीटीएच 9802 अध्याय के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीटीएच 9802 हेतु इस विशेष श्रेणी, बीसीडी को टेरिफ में 150 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार, किसी भी वस्तु के लिए बाउंड रेट डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन टैरिफ और अधिकतम दरें इस संसद द्वारा तय की जाती हैं। इसलिए, इस सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत टैरिफ दर का 160 प्रतिशत, जो एक सीमा के रूप में कार्य करता है, संसद द्वारा अनुमोदित होता है। पुनः, दुर्लभ खनिजों के आयात के संबंध में मेरा कहना है कि ये खनिज इस देश में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, खान मंत्रालय का मानना है कि हमें इन्हें रियायती या शून्य प्रतिशत दरों पर प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसीलिए इसके सीमा शुल्क को कम कर दिया गया है। यह भी मांग की गई थी कि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में राहत दी जाए। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मार्च, 2024 में ही देश भर में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। पुनः उत्तर प्रदेश राज्य से सिंथेटिक मेन्थॉल पर जीएसटी दर बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था ताकि इस देश में उत्पादित प्राकृतिक मेन्थॉल के मूल्यों को संरक्षण दिया जा सके। इस वित्त विधेयक में प्राकृतिक मेन्थॉल के लिए एक अलग एचएस कोड बनाने का प्रस्ताव है और इसलिए इसके बाद जीएसटी परिषद् इस मामले पर विचार कर अपना निर्णय ले सकती है। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगाए जाने से पहले से ही हर स्टेट में प्री-जीएसटी टैक्स लगता था। 31वीं मीटिंग में फिर 37वीं मीटिंग में और इसके बाद 47वीं मीटिंग में भी इस पर चर्चा हुई। इस प्रकार जीएसटी काउंसिल में तीन बार इस पर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान है, जिसमें से 9 प्रतिशत राज्यों को और 9 प्रतिशत केन्द्र को जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक सौ रुपए जीएसटी में से 50 रुपए राज्य को तुरंत चला जाता है और केन्द्र को मिले शेष 50 रुपये में से भी 29 रुपए 55 पैसे राज्य को चले जातें है। यानी हर सौ रुपए में से 74 रुपए राज्य को चले जाते हैं। ■

'18वीं लोकसभा' के गठन के बाद संसद का पहला बजट सत्र समाप्त

केंद्रीय बजट के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट भी लोकसभा में पेश किया गया

बजट सत्र 2024 के दौरान लोकसभा में कामकाज लगभग 136% और राज्यसभा में कामकाज लगभग 118% हुआ

संसद का बजट सत्र 2024, 22 जुलाई को शुरू हुआ और 9 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहला बजट सत्र था और 23 जुलाई को केंद्रीय बजट के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का बजट भी लोकसभा में पेश किया गया।

बजट पेश होने के बाद दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस पर लोकसभा में आवंटित 20 घंटों के मुकाबले 27 घंटे 19 मिनट तक और राज्यसभा में आवंटित 20 घंटों के मुकाबले 22 घंटे 40 मिनट तक चर्चा हुई। वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट पर सामान्य चर्चा और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों पर चर्चा 2024-25 तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर भी एक साथ चर्चा की गई और वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा के साथ ही लोकसभा में इन्हें पारित कर दिया गया।

लोक सभा में रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई तथा उनका अनुमोदन किया गया। इसके बाद मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों पर 5 अगस्त को सदन में मतदान कराया गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 05.08.2024 को ही लोक सभा में प्रस्तुत, विचार और पारित किया गया। वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 पर 6 और 7 अगस्त को लोकसभा में विचार किया गया और पारित किया गया।

राज्यसभा में आवास एवं शहरी कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई। राज्यसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों और वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 को 08.08.2024 को वापस कर दिया।

लोकसभा ने 09.08.2024 को विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जा, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन एवं नियंत्रण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक या आकस्मिक मामलों के लिए 'भारतीय वायुयान विधेयक, 2024' पारित किया।

'आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारी' और 'अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों की मौत की दुःखद घटना' पर अल्पकालिक चर्चा क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में की गई।

देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल की हानि तथा केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर क्रमशः लोक सभा और राज्यसभा में चर्चा की गई।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को 09.08.2024 को संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ भेजा गया है।

बजट सत्र 2024 के दौरान लोकसभा में कामकाज लगभग 136% और राज्यसभा में कामकाज लगभग 118% हुआ।

लोकसभा में पेश किए गए विधेयक

- वित्त (सं.2) विधेयक, 2024
- जम्मू और कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, 2024
- भारतीय वायुयान विधेयक, 2024
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
- गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024

- विनियोग (सं.2) विधेयक, 2024
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
- समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक, 2024
- द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल, 2024
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक

- तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
  बॉयलर विधेयक, 2024

लोकसभा में पारित विधेयक

- जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2024
- विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2024
- वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024
- भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

राज्यसभा में पारित विधेयक

- जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2024
- विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2024, जैसाकि लोकसभा में पारित किया गया।
- वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024

संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक

- जम्मू-कश्मीर विनियोग (सं.3) विधेयक, 2024
- विनियोग (सं.2) विधेयक, 2024, जैसाकि लोकसभा में पारित किया गया।
- वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024

राज्यसभा में वापस लिए गए विधेयक

- वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 24×7 जल आपूर्ति परियोजना का किया लोकार्पण

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चार अगस्त को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मनीमाजरा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई 24×7 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा सांसद श्री सतनाम सिंह संधू, केन्द्रीय गृह सचिव और आसूचना ब्यूरो के निदेशक सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मनीमाजरा की जल आपूर्ति परियोजना से एक लाख से ज्यादा आबादी को फायदा मिलेगा और 855 एकड़ में फैली इस बस्ती को 22 किलोमीटर लंबे नई पाइपलाइन से अब चौबीसों घंटे पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यहां दो विशाल रिजर्वायर बनाकर 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रबंध किया गया है। श्री शाह ने यह भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से लीकेज का खर्च भी अब उपभोक्ताओं पर नहीं आएगा, घर में लीकेज होने का भी तुरंत पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी का प्रेशर सुनिश्चित करने के लिए VFD पंप भी लगाया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पानी सभी के जीवन के लिए प्राण होता है और पानी के बगैर जीवन असंभव है। उन्होंने कहा कि पानी अगर दूषित हो और ज़रूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयों और रोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आज से पूरे क्षेत्र के लोगों को सबसे आधुनिक फ़िल्टर प्लांट से चौबीसों घंटे फ़िल्टर पानी मुहैया कराने की शुरुआत हो रही है।

श्री शाह ने कहा कि देश के नागरिकों का यह संकल्प देश को विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बच्चे द्वारा लिया गया अन्न का अपमान न करने का संकल्प या रोज माता-पिता के चरण स्पर्श करने का संकल्प, एक व्यापारी का टैक्स चोरी न करने का संकल्प या लोगों का ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प देश को मजबूत करता है, उसे आगे बढ़ाता है।

श्री शाह ने कहा कि 130 करोड़ लोगों द्वारा लिया गया एक कदम देश को 130 करोड़ कदम आगे ले जाने के समान है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ये ही चमत्कार करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ संकल्पवान लोग भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और आज चंडीगढ़ में हमने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।

खादी की बिक्री बढ़ी 400 प्रतिशत, पहली बार कारोबार डेढ़ लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जुलाई को कहा कि खादी की बिक्री में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार डेढ़ लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 112वीं कड़ी में श्री मोदी ने देशवासियों से खादी के कपड़े खरीदने का आग्रह भी किया।

उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए आनंद महसूस हो रहा है कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार डेढ़ लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। सोचिए, डेढ़ लाख करोड़ रुपये! और जानते हैं, खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है? 400 प्रतिशत।" प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी और हैंडलूम उत्पादों की बढ़ती ब्रिक्री, बड़ी संख्या में रोजगार के नये अवसर भी पैदा कर रही है और चूंकि, इससे महिलाएं सबसे ज्यादा जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है।

अगस्त के महीने को आजादी का महीना करार देते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों के पास भांति-भांति के वस्त्र होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने यदि खादी के वस्त्र नहीं खरीदे हैं, तो वे इस साल से ही इनकी खरीदारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा, "अगस्त का महीना आ गया है। यह आजादी मिलने का महीना है, क्रांति का महीना है। इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा खादी खरीदने के लिए।"

'मन की बात' की इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों के सेवन से जुड़ी चिंताओं पर भी बात की। उन्होंने लोगों से भारत को नशा मुक्त बनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि नशे की लत के शिकार लोगों की मदद के लिए सरकार ने 'मानस' नामक अभियान की शुरुआत की है, जो मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही 'मानस' की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया था और सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 भी जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर पुनर्वास से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थों से जुड़ी जानकारी इस नंबर पर साझा करने का आग्रह भी किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत के साथ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका मिलता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे उन्हें प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने उन भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की, जिन्होंने हाल ही में आयोजित गणित ओलंपियाड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले गणित की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ। अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के छात्रों ने बहुत शानदार

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 28 जुलाई, 2024 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 112वें संस्करण को सुना।

इस अवसर पर श्री नड्डा ने एक्स पर लिखा, "28 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 112वें संस्करण को सुना। 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी व्यक्तियों और विभिन्न पहलों की सफलता की गाथा पर हमारा ध्यान आकर्षित करते आये हैं। ऐसे ही 'हर घर तिरंगा' और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे सामाजिक अभियान और पर्यावरण जागरूकता अभियान उनके प्रयासों के उदाहरण हैं। हमारी सरकार ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 'मैदाम' को शामिल करने और महान अहोम योद्धा लछित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण में स्पष्ट है। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने में हमारे समर्पित प्रयासों के प्रमाण हैं।" ■

प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है।''

असम के चराईदेउ मैदाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल

प्रधानमंत्री ने असम के 'मैदाम' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की सराहना की और कहा कि असम के चराईदेउ मैदाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं, लेकिन पूर्वोत्तर की पहली साइट होगी।

उन्होंने कहा कि आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि चराईदेउ मैदाम आखिर है क्या, और ये इतना खास क्यों है। चराईदेउ का मतलब है shining city on the hills, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। यह अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के शव और उनकी कीमती चीजों को पारंपरिक रूप से मैदाम में रखते थे।

श्री मोदी ने कहा कि मैदाम टीले नुमा एक ढांचा होता है, जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे एक या उससे ज्यादा कमरे होते हैं। ये मैदाम अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य लोगों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका बहुत यूनिक है। इस जगह पर सामुदायिक पूजा भी होती थी।

उन्होंने कहा कि अहोम साम्राज्य के बारे में दूसरी जानकारियां आपको और हैरान करेंगी। 13वीं शताब्दी के शुरू होकर यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला। इतने लंबे कालखंड तक एक साम्राज्य का बने रहना बहुत बड़ी बात है। शायद अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और विश्वास इतने मजबूत थे कि उसने इस राजवंश को इतने समय तक कायम रखा।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि इसी वर्ष 9 मार्च को मुझे अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक, महान अहोम योद्धा लसित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला था। इस कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हुए मुझे अलग ही अनुभव हुआ था। लसित मैदाम में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब चराईदेउ मैदाम के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने अपनी यात्राओं में इस जगह को जरूर शामिल करिएगा।

दुनिया में बाघों की 70 प्रतिशत आबादी भारत में

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दुनिया में बाघों की 70 प्रतिशत आबादी भारत में है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे लोगों को गर्व होगा। इस संदर्भ में श्री मोदी ने 'बाघ मित्रों' की प्रशंसा की, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि जानवरों के निवास वाले क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्ष नहीं हो।

उन्होंने कहा, "बाघों की आबादी बढ़ने के साथ-साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है।" श्री मोदी ने कहा कि इसमें भी सामुदायिक प्रयासों से बड़ी सफलता हासिल की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "महाराष्ट्र का तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहां के स्थानीय समुदायों, विशेषकर गोंड और माना जनजाति के हमारे भाई-बहनों ने इको-टूरिज्म की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहां बाघों की गतिविधियां बढ़ सके।"

स्वतंत्रता दिवस के करीब आने के साथ ही उन्होंने लोगों से वेबसाइट 'हरघरतिरंगा डॉट कॉम' पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह करते हुए कहा कि 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, 'हर घर तिरंगा अभियान'। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में 'हर घर तिरंगा अभियान' के लिए सबका जोश ज्यादा रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है।

श्री मोदी ने कहा कि पहले की तरह इस साल भी आप 'harghartiranga.com' पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। ■

प्रधानमंत्री ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में नए पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आठ अगस्त को बांग्लादेश में नवगठित अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद संभालने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को बधाई दी। श्री मोदी ने पड़ोसी देश में स्थिति सामान्य होने और हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की कामना की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। शांति, सुरक्षा और विकास के साथ दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता जारी रहेगी।" ■

प्रधानमंत्री ने एससी/एसटी के भाजपा सांसदों प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौ अगस्त को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण तथा उनके सशक्तीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया।

श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज एससी/एसटी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया।"

केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया है। भाजपा के एसटी/एससी सांसदों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और स्पष्ट रूप से कहा कि अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

श्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर कहा, "आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा के एससी/एसटी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया।"

उल्लेखनीय है कि एसटी/एससी समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने संयुक्त रूप से एसटी/एससी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर गौर करेंगे। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

वायनाड (केरल) में 10 अगस्त, 2024 को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कलपेट्टा (वायनाड) में 10 अगस्त, 2024 को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 27 जुलाई, 2024 को अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 03 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति भवन (नई दिल्ली) में 01 अगस्त, 2024 को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री फाम मिन्ह चिन्ह के औपचारिक स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली) में 11 अगस्त, 2024 को किसानों एवं वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 20 अगस्त, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह